नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

चक्काजाम कर छात्राओं ने मांगा स्कूल के लिए रास्ता

सिवनी में पक्की सड़क के लिए जेन अल्फा उग्र

नवभारत न्यूज

सिवनी, 24 अगस्त. छिंदवाड़ा मार्ग पर ग्राम कोहका गोह के पास सोमवार दोपहर खराब सड़क को लेकर पीपरड़ाही हाईस्कूल के नाराज छात्र छात्राओं ने चक्काजाम कर दिया.

विद्यार्थियों के मुताबिक चारगांव-जमुनिया से स्कूल तक जाने वाला रास्ता कच्चा है और बारिश में इसकी हालत और बिगड़ जाती है. सड़क पर जगह-जगह कीचड़ और गड्ढे हैं, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है. उन्हें कपड़े और किताबें बचाकर इस रास्ते से स्कूल पहुंचना पड़ता है. लंबे अर्से से से यह समस्या बनी हुई है, मगर इसका अब तक कोई स्थायी हल नहीं किया गया. विद्यार्थियों के चक्काजाम के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई. दोपहर 11 बजे से शुरू हुआ घटनाक्रम एक घंटे से अधिक समय तक चला.

सूचना मिलने पर, तहसीलदार, एसडीएम, डीईओ सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने विद्यार्थियों से बातचीत की और सड़क से हटने की अपील की. स्कूल प्रबंधन ने भी उनसे बातचीत की लेकिन छात्र सड़क सुधार की मांग पर अड़े रहे. उनका कहना था कि स्कूल तक पहुंचने वाले रास्ते को ठीक करने के लिए ठोस पहल होने के बाद ही वे आंदोलन खत्म करेंगे, हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों के समझाने के बाद मार्ग खालीकर स्कूल लौट गये.

परीक्षा में बांटा गलत पेपर, छात्रों ने कर दिया घेराव

रानी दुर्गावती यूनीवर्सिटी में उग्र प्रदर्शन

नवभारत न्यूज

जबलपुर, 24 अगस्त. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में शनिवार को आयोजित बीकॉम फर्स्ट ईयर की परीक्षा में प्रबंधन की गंभीर लापरवाही उजागर हुई. यहां परीक्षार्थियों को निर्धारित विषय बिजनेस इकोनॉमिक्स के बदले बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर का अपरिचित प्रश्न पत्र बांट दिया गया.

छात्रा भूमिका शुक्ला सहित अन्य विद्यार्थियों ने पूरे शैक्षणिक सत्र के पाठ्यक्रम से एक भी सवाल न मिलने पर परीक्षा हाल में कड़ा विरोध दर्ज कराया. मौके पर उचित समाधान न निकलने पर सभी छात्र कक्ष छोड़कर बाहर आ गए और सोमवार को प्रशासनिक भवन पर उग्र प्रदर्शन करते हुए जनरल प्रमोशन देने की मांग रखी. पीड़ित छात्र दल ने कुलसचिव डॉ. रविशंकर सोनवाल को पत्र दिया, जिस पर उन्होंने परीक्षा नियंत्रक से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और किसी को भी फेल न करने का आश्वासन दिया.

विद्यार्थियों का कहना है कि प्रशासन अपनी व्यवस्थागत खामी का बोझ जबरन उनके ऊपर डाल रहा है. छात्र प्रतिनिधियों ने विवि प्रशासन के समक्ष मजबूती से पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि जिस पाठ्यक्रम का अध्यापन पूरे वर्ष कराया ही नहीं गया, उसके आधार पर किसी भी छात्र की योग्यता का आकलन करना नियम विरुद्ध है. कुलसचिव ने मामले की संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए आश्वस्त किया कि किसी भी निर्दोष विद्यार्थी का साल खराब नहीं होने दिया जाएगा. विवि प्रशासन अब प्रश्न पत्र तैयार करने, उसकी मॉडरेशन व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों तक गोपनीय पैकेट पहुंचाने वाली पूरी प्रक्रिया की पड़ताल कर रहा है. प्रश्न पत्र वितरण में किस स्तर पर मानवीय या तकनीकी चूक हुई, उसकी जवाबदेही तय की जा रही है. जांच रिपोर्ट आते ही जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक वैधानिक कदम उठाए जाएंगे.

एक नजर में

बस- आटो की भिड़ंत में बहन की मौत, भाई गंभीर

सीधी. रक्षाबंधन से पहले सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. ग्राम सपही बांध के पास सोमवार को तेज रफ्तार बस और ऑटो की जोरदार भिड़ंत में स्कूल जा रहे तीन बच्चे घायलहो गए.

दुष्कर्म के आरोपी ने पुल से कूदने की दी धमकी

भिंड. प्रेमिका से जन्मी बच्ची को अपनी संतान बताते हुए उसे साथ ले जाने की मांग कर रहा दुष्कर्म का आरोपी चंबल नदी के पुल पर चढ़ गया. उसने नीचे कूदने की धमकी दी. सूचना मिलते ही मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश पुलिस मौके पर पहुंची. करीब एक घंटे की समझाइश के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतर आया.

सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, तीन गिरफ्तार

डबरा. भितरवार के बसई गांव में 21 वर्षीय युवती के साथ राइफल की नोक पर घर से ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़िता के आरोप के आधार पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. सोमवार को पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

स्किल करेंसी, इनोवेशन इकोनामी

1 संस्थाओं को कौशल, शोध, नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनाना होगा

2 राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 24 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत के पास अपने सामर्थ्य से हर प्रकार की चुनौती से निपटने की क्षमता है. जिस प्रकार रामायण में जामवंत ने समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी को उनकी शक्ति से परिचित कराया था, उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को उसके सामर्थ्य से परिचित कराया है.

आज स्किल नई करेंसी है और इनोवेशन नई इकोनामी. हमारी संस्थाओं को कौशल, शोध, नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनना होगा. पब्लिकेशन से लेकर पेटेंट तक, पेटेंट से प्रोटोटाइप तक और प्रोटोटाइप से लेकर एंटरप्राइज की इकोनामिक और नॉलेज वैल्यू चैन की स्थापना करनी होगी. मध्यप्रदेश अवसरों की धरती है और प्रतिभाशाली युवा, प्राकृतिक संसाधन, कृषि शक्ति, उद्यमशीलता और औद्योगिक क्षमता हमारे संसाधन है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में

कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन्स फॉर समृद्ध मध्यप्रदेश :2047 पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे. वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस की थीम पर आयोजित कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश में स्थित केन्द्रीय संस्थाओं की समृद्ध मध्यप्रदेश 2047 के लक्ष्य प्राप्ति में भागीदारी और सहभागिता सुनिश्चित करना है. कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में विभिन्न संस्थाओं के बीच एमओयू का आदान-प्रदान हुआ.मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश के विभिन्न केंद्रीय संस्थानों के प्रतिनिधियों का एक मंच पर एकत्र होना मप्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है. इससे संस्थानों को अपनी उपलब्धियां, विशेषज्ञता और भविष्य की योजनाएं साझा करने के साथ प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप योगदान देने का अवसर मिलेगा.संस्थानों में उपलब्ध ज्ञान और तकनीक का लाभ प्रयोगशालाओं और परिसरों तक सीमित न रहकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए.

आज एआई पर बात करना फैशन बन गया : सीएस

मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर बहुत अधिक फोकस है, आज एआई के बारे में बातें करना एक फैशन बन गया है. ये सही है कि आने वाले समय में एआई बड़ा बदलाव लाने वाला है, लेकिन इसका असर कितना और किस रूप में होगा, इसके बारे में अभी से अनुमान लगाना मुश्किल है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि प्रदेश की युवा आबादी को किस तरह तैयार किया जाए. उन्होंने कहा कि हमें हमारे युवाओं को एआई की चुनौती का सामना करने के उद्देश्य से कौशल सम्पन्न बनाना होगा. सभी केन्द्रीय संस्थान अपने-अपने क्षेत्र में संकल्प लें और परिणाम देने के उद्देश्य से कार्य करें. विकसित मप्र की जिम्मेदारी सिर्फ शासन की नहीं, बल्कि हम सभी की है.

14 लाख अंत्योदय परिवार से त्योहार से पहले सरकार ने छीनी मिठास

- राशन दुकानों पर शक्कर मिलना हुई बंद
- केंद्र ने सब्सिडी बंद की तो मप्र सरकार ने शक्कर रोकी

कन्हैया लोधी

भोपाल, 24 अगस्त. देश और प्रदेश में बढ़ते शक्कर के दाम ने आम से खास लोगों को भी परेशान करना शुरू कर दिया है. इस बीच मप्र में 14 लाख से अधिक अंत्योदय परिवार की थाली से मिठास छिन गई है. जी हां. मप्र सरकार ने अब प्रदेश के अंत्योदय परिवार को शक्कर देना बंद कर दिया है. केंद्र सरकार ने शक्कर पर जैसे ही सब्सिडी देना बंद किया, मप्र सरकार ने भी इस योजना से किनारा कर लिया. नतीजा ये हुआ है कि मप्र में अप्रैल से ही अंत्योदय परिवार को शक्कर मिलना बंद हो गया है.

दरअसल प्रदेश में अंत्योदय परिवार को उनकी जरुरत की राशन के साथ एक किलो शक्कर भी रियायती दामों पर दिया जा रहा था. ये शक्कर अंत्योदय परिवार को महज 20 रुपए किलो के हिसाब से दिया जा रहा था. प्रदेश के 27 हजार 800 से अधिक राशन दुकानों के माध्यम से ये शक्कर दिया जा रहा था. इसके लिए केंद्र सरकार प्रति किलो 18.50 रुपए सब्सिडी दे रही थी. टेंडर में मिले दाम का बाकी

हिस्सा राज्य सरकार अपने खजाने से वहन करती थी. इसे इस तरह समझें यदि अंत्योदय परिवार को शक्कर देने के लिए राज्य सरकार टेंडर जारी करती थी और उसमें दाम प्रति किलोग्राम 45 रुपए आता था तो अंत्योदय परिवार से प्रति किलो के हिसाब से 20 रुपए और केंद्र सरकार की 18.50 रुपए प्रति किलोग्राम सब्सिडी मिलाकर कुल 38.50 रुपए होते हैं, तो बाकी 6.50 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार अपने खजाने से देती थी, लेकिन जैसे ही मार्च के बाद केंद्र सरकार ने सब्सिडी देना बंद किया, मप्र सरकार ने भी अंत्योदय परिवार को शक्कर देना बंद कर दिया. मप्र सरकार पहले अंत्योदय परिवार को 15 हजार मीट्रिक टन से अधिक शक्कर रियायती दामों पर उपलब्ध कराती थी.

क्यों आई गरीबों को शक्कर की याद

दरअसल देश में शक्कर के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. खुले मार्केट में शक्कर के दाम अब लगभग 70 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचने लगा है. इधर त्यौहारी सीजन शुरू हो रहा है, बिना मिठास के किसी भी त्यौहार की तैयारी अधूरी मानी जाती है. दाम बढ़ने से शक्कर अब गरीबों की पहुंच से दूर होने का अंदेशा बढ़ गया है. ऐसे में गरीब को एक किलोग्राम ही सही यदि महज 20 रुपए में मिल जाए, तो यह भी राहत से कम नहीं थी, लेकिन अब ना तो राहत मिलेगी और न ही कोई रियायत.

फिलहाल योजना शुरू होने की संभावना नहीं

अंत्योदय परिवार को प्रति परिवार एक किलोग्राम शक्कर देने की योजना फिलहाल शुरू होने की संभावना नजर नहीं आ रही है. ये इसलिए कि इस मद में राज्य सरकार ने राशि का कोई प्रावधान नहीं किया है. यानी ये योजना अब मप्र में लगभग बंद हो गई है.

'विधायक मेरा मामा है' कहकर शराब बेचने की धौंस, ग्रामीणों ने किया विरोध

नवभारत न्यूज

खंडवा, 24 अगस्त. पिपलोद थाना क्षेत्र के खिड़गांव में शराबबंदी की मुहिम के दौरान एक युवक पर राजनीतिक रसूख का हवाला देकर शराब बिक्री जारी रखने का आरोप लगा है. ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार, डायरी सिस्टम के जरिए शराब बेच रहे युवक ने खुद को विधायक कंचन तनवे का भांजा बताया और कार्रवाई की चेतावनी देने पर धौंस दिखाई.

ग्रामीणों ने सदानंद नाम के युवक को डायरी पर शराब

बेचते हुए रोकने की कोशिश की. समझाइश देने पर उसने कथित तौर पर विधायक कंचन तनवे और उनके पति मुकेश तनवे को अपना मामा-मामी बताया. विरोध बढ़ने पर युवक ने मुकेश तनवे को फोन लगाया, हालांकि फोन उनके पीए सुनील ने उठाया. युवक की विधायक या उनके पति से सीधे बात नहीं हो सकी.

इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता ममता मोरे ने संबंधित शराब ठेकेदार से गांव में शराब बिक्री बंद करने को कहा. ठेकेदार ने गांव में शराब नहीं बेचने की बात कही.

सहायक जिला आबकारी अधिकारी चंदनसिंह मीणा ने कहा कि शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. उनके मुताबिक लाइसेंसी दुकान के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से शराब बिकवाना अवैध है. शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पचमढ़ी में नाबालिग से गैंगरेप

रिपोर्ट दर्ज होते ही 6 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

नर्मदापुरम, 24 अगस्त . मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी में नाबालिग के साथ कथित गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि परिचित युवकों ने ही नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया हैं.

नाबालिक एक युवक के साथ पचमढ़ी घूम रही थीं तभी उनके परिचित युवक आ गए और बहला-फुसलाकर दोनों को घुमाने के बहाने सुनसान स्थान पर ले गए. जहां आरोपियों ने नाबालिक से सामूहिक दुष्कर्म किया. एडिशनल एसपी अभिषेक राजन ने बताया की घटना 19 अगस्त की है. घटना के

बाद नाबालिग और उसका मित्र

डर गए और उन्होंने तत्काल परिजनों को जानकारी नहीं दी. बाद में जब परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो 23 अगस्त को पचमढ़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. पीड़िता और आरोपी एक स्थान के रहने वाले है.

छह घंटे के अंदर टीमों ने आरोपियों को घेरा

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की अलग-अलग टीमे बनाई गई. जिन्होंने आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब छह घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नाबालिग की पहचान से जुड़ी जानकारी को गोपनीय रखा है. प्रकरण में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

पेट्रोल पंप में साझेदारी के नाम पर 60 लाख की धोखाधड़ी

- इंदौर में दंपति पर एफआईआर
- पूर्व पार्षद के भतीजे ने लगाए एग्रीमेंट नहीं करने के आरोप

नवभारत न्यूज

इंदौर, 24 अगस्त . द्वारकापुरी थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप में साझेदारी देने के नाम पर 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में दंपति के खिलाफ मामला दर्ज किया है. शिकायत पूर्व पार्षद के भतीजे श्रीकांत लड्ढा ने की है.

आरोप है कि 2017 से 2022 के बीच अलग-अलग किस्तों में बैंक खातों के जरिए रकम लेने के बावजूद साझेदारी का एग्रीमेंट नहीं किया गया और पैसे भी वापस नहीं लौटाए गए. पुलिस के अनुसार गुमाश्ता नगर निवासी श्रीकांत लड्ढा ने शिकायत में बताया कि आरोपी सावन दुबे और उसकी पत्नी पूजा दुबे से उनके पारिवारिक संबंध थे. इसी दौरान 2017 के अंत में दंपति ने श्रीकांत के पिता को फ्यूल स्टेशन में निवेश और साझेदारी का प्रस्ताव दिया. जिस पर अलग-अलग किस्तों में दंपति के बैंक खातों में करीब 60 लाख रुपए ट्रांसफर किए. आरोप है कि रकम लेने के बाद साझेदारी को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया.

राहत | सुप्रीम कोर्ट का अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला

नए नियम पुराने कर्मियों पर लागू नहीं हो सकते

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 24 अगस्त. नवभारत न्यूज. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सेवा नियमों में बदलाव से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि बाद में किए गए संशोधन या जारी आदेशों की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिससे उन कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी हो, जिन्होंने पहले लागू नियमों के मुताबिक अपनी योग्यता हासिल की थी. जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने तमिलनाडु पर्यटन विभाग से जुड़े मामले में यह टिप्पणी की.

मामला आर.जे. गजेंद्र कुमार का था, जिन्हें 1983 में पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर तमिलनाडु पर्यटन विभाग में जूनियर असिस्टेंट नियुक्त किया गया था. बाद में सरकार ने इस तरह प्राप्त योग्यताओं को विभिन्न आदेशों के जरिए मान्यता दी. वर्ष 2000 में डिस्टेंस एजुकेशन से मिली डिग्री को नियमित डिग्री के बराबर भी माना गया. कुमार को 2011 में टूरिस्ट ऑफिसर पद पर पदोन्नति मिली और उनकी सेवा 5 अगस्त 2011 से नियमित की गई. लंबे समय तक उनकी शैक्षणिक पात्रता या पदोन्नति पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई. हालांकि, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म पद पर पदोन्नति का दावा करने पर वर्ष 2020 में सरकार ने उनकी योग्यता पर सवाल उठाया. विभाग ने बाद में जारी आदेशों और स्पष्टीकरणों का हवाला देते हुए कहा कि उनकी शिक्षा निर्धारित 10+2+3 व्यवस्था के अनुरूप नहीं थी.

हाईकोर्ट का आदेश पलटा

मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कुमार के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन खंडपीठ ने उसे पलट दिया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. शीर्ष अदालत ने खंडपीठ का आदेश रद्द करते हुए कहा कि जिस समय संबंधित योग्यता हासिल की गई थी, उस समय वह लागू नियमों के तहत स्वीकार्य थी. बाद में हुए बदलावों के आधार पर उसे पिछली अवधि से अमान्य नहीं माना जा सकता.

सीएम के फर्जी लेटरहेड से डॉक्टर का ट्रांसफर

अलीराजपुर. मुख्यमंत्री के नाम और फर्जी लेटरहेड का इस्तेमाल कर आयुष चिकित्सा अधिकारी का स्थानांतरण आदेश तैयार कर सोशल मीडिया पर भेजने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जांच के दौरान मोबाइल से मिले 45 हजार रुपए के ऑनलाइन लेनदेन के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. सीएमएचओ डॉ. राजेश अतुलकर की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. आरोपी ने मुख्यमंत्री के लेटरहेड और फोटो का इस्तेमाल कर आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ. निर्मला निगवाल का उदयगढ़ से सोंडवा स्थानांतरण किए जाने संबंधी फर्जी आदेश तैयार किया था.

कैलारस कारखाने पर डीएम के दावे से बवाल

नवभारत न्यूज

मुरैना, 24 अगस्त . जिले के कैलारस सहकारी शक्कर कारखाने को पुनर्जीवित कर चालू करने का निर्णय कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय के आमरण अनशन से पहले ही लिए जाने संबंधी मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के कथित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है.

विधायक उपाध्याय ने कलेक्टर को हस्तलिखित पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि कलेक्टर जैसे पद पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बयान देना पद की गरिमा के खिलाफ है. उन्होंने सवाल

बयान पर भड़के विधायक

किया कि जब उन्होंने शक्कर कारखाने को पुनः चालू कराने के लिए आमरण अनशन का लिखित पत्र दिया था, तब कलेक्टर ने उन्हें सरकार के निर्णय से अवगत क्यों नहीं कराया और आंदोलन स्थल पर पहुंचकर इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं दी.विधायक ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर इस तरह का बयान जारी कर जनता को गुमराह किया जा रहा है. उन्होंने कलेक्टर से अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है.

उपाध्याय ने पत्र में चेतावनी दी है कि वह कलेक्टर के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने के साथ न्यायालय में मानहानि का मामला भी दायर करेंगे. विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि कलेक्टर ने सरकार के कहने पर बयान जारी किया है, ताकि कैलारस शक्कर कारखाना चालू कराने का श्रेय उन्हें और कांग्रेस को नहीं मिल सके. दरअसल मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि यह कहना गलत है कि विधायक पंकज उपाध्याय के अनशन के बाद शक्कर कारखाना चालू करने का निर्णय लिया गया, यह निर्णय पहले ही ले लिया गया था.